release in N-OYT General category in Nehru Place Exchange is 5.3.1991.

(b) and (c) Out of a total of 44 exchange area in Delhi, 9 exchange areas are behind even Nehru Place Exchange in the matter of clearance of waiting list.

(d) It is planned to provide telephones to all the registrants as on 1.8.95 for Nehru Place Exchange Before 31.3.1996.

Mining of Diamonds Under Forest Land

*298. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) What is the legal status of mining/ extradition of diamonds falling under the jurisdiction of forest land;

(b) whether a large number of companies have applied for mining of diamonds under the forest land in Madhya Pradesh and Orissa; and

(c) if so, what are the names of these companies and in how many cases the permission has been granted with detailed terms and conditions laid-down by Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Prior approval of the Central Government is required under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for any non-forest purpose including mining of diamonds.

(b) and (c) No proposal under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for mining of diamonds in Madhya Pradesh or Orissa is pending with the Ministry as on 31.7.1995.

आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना हेतु प्रस्ताव

*299. श्री अजीत जोगी:
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1994-95 के दौरान देश के आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए खाद्य प्रसंस्करण एककों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल 1994 से मार्च, 1995 के दौरान 526 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए जिनमें लगभग 6229 करोड़ रुपए के निवेश तथा लगभग 71218 व्यक्तियों को रोजगार देने का उल्लेख है। इनमें से 212 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन केवल पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना से संबंधित हैं। इनमें 2687 करोड़ रुपए का निवेश तथा 25098 व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था है।

(ग) अगस्त, 1991 से लेकर मार्च, 1995 तक पिछड़े क्षेत्रों में 188 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित की गई हैं। जिनमें 1951 करोड़ रुपए के निवेश तथा 22100 व्यक्तियों को रोजगार देने का उल्लेख है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपमार्गों का निर्माण करने के लिए निर्धारित मानदंड

300. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपमार्गों के निर्माण के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) मध्य प्रदेश में आगामी तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रति वर्ष निर्मित किए जाने वाले उपमार्गों का ब्यौरा क्या है;